सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

विकसित राजस्थान @2047

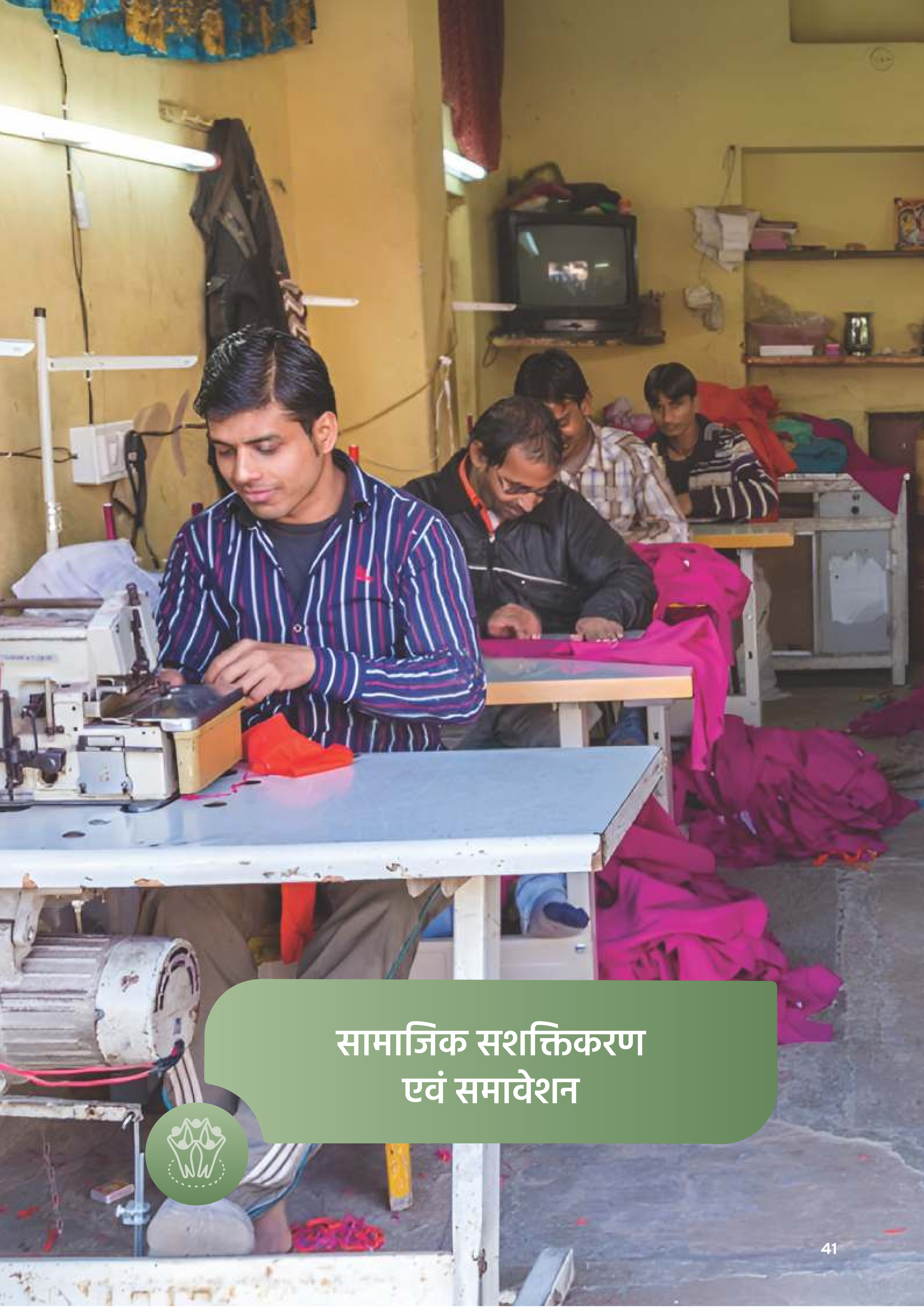

सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन

सामाजिक सुरक्षा और समावेशन
की ओर अग्रसर

राजस्थान **समावेशी सामाजिक विकास** के लिए प्रतिबद्ध है, **जो वंचित समुदायों, महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों, अल्पसंख्यकों, युवाओं और विशेष योग्यजनों** के कल्याण को सुनिश्चित करता है।

जनजातीय, अल्पसंख्यक, श्रम, महिला एवं बाल विकास और युवा मामलों को समर्पित विभागों के साथ **राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और लैंगिक समानता** पर ध्यान केंद्रित करता है। नीतियाँ एवं योजनाएं **आर्थिक उत्थान, सामाजिक न्याय और कार्यबल सशक्तिकरण** को लक्षित करती हैं, जिससे **2047 तक एक प्रगतिशील और समावेशी राजस्थान का निर्माण** होगा।

अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या : **92.38 लाख**
(जनगणना 2011)
(राज्य की जनसंख्या का 13.5%)

अनुसूचित जाति जनसंख्या : **122.21 लाख**
(जनगणना 2011)
(राज्य की जनसंख्या का 17.83%)

अल्पसंख्यक जनसंख्या
78.18 लाख
(जनगणना 2011)
(राज्य की कुल जनसंख्या का 11.41%)

वर्ष 2014 में बाल अधिकारों के लिए समर्पित विभाग की स्थापना

पांचवीं अनुसूची जनजातीय प्रशासन हेतु
राजस्थान को विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है

महिलाओं हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा,
कौशल विकास और सुरक्षा पर केंद्रित नीतियाँ

श्रम विभाग उचित पारिश्रमिक
और औद्योगिक सौहार्द सुनिश्चित करता है

'राजस्थान कौशल नीति 2025'
के तहत युवाओं के
कौशल विकास को बढ़ावा

जनजातीय उत्थान
वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना

वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक
मामलात विभाग की स्थापना

युवाओं के स्वास्थ्य और उत्कृष्टता
को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक खेल अवसंरचना

विज़न 2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान अधिक **समतापूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा**, जहां सभी के लिए विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अल्पसंख्यक **सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप** से सशक्त होंगे और महिलाएं एवं बच्चे, **अवसरों तक समान पहुँच** प्राप्त कर सम्मानजनक एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे।

एक सक्षम **कार्यबल एवं दक्ष युवा** आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक होंगे। **खेल, फिटनेस एवं प्रतिभा विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित कर वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करेगा।**

प्रमुख क्षेत्र

कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना

राजस्थान शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

विशेष योग्यजनों का सशक्तिकरण

समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का विस्तार।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

बुजुर्गों के लिए केयर होम्स, स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग और सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित किये जाएंगे।

महिला एवं बाल कल्याण

महिलाओं और बच्चों जिसमें विशेषकर सबसे कमजोर समूह भी शामिल हैं के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

महिलाओं और बच्चों के बेहतर जीवनरक्षण एवं समग्र विकासात्मक परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना।

भिक्षुक मुक्त राजस्थान

भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए भिक्षुकों की पहचान कर उन्हें आश्रय, भोजन, कौशल विकास और एनजीओ के सहयोग से सामाजिक पुनःस्थापन के माध्यम से पुनर्वासित किया जाएगा।

डीनोटीफाइड जनजाति (DNT) कल्याण

डीनोटीफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कल्याणकारी योजनाओं, कौशल विकास और मुख्यधारा में समावेशन के माध्यम से सुधारा जाएगा।

अल्पसंख्यक उत्थान

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा देना, आजीविका के अवसर प्रदान करना एवं अवसंरचना का विकास करना।

श्रमिक अधिकार और कल्याण

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देना और सशक्त श्रम कानून लागू करना।

युवा और खेल विकास

विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना, एथलीट सपोर्ट और प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों में निवेश करना।

सतत् पर्यटन और स्वदेशी पहचान

जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना।

जलवायु अनुकूलन और सामाजिक कल्याण

जलवायु अनुकूलन रणनीतियों, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्यवाही में महिला भागीदारी क्रियान्वित करना।

ट्रांसजेंडर कल्याण

ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए पहचान पत्र जारी करना, कौशल प्रशिक्षण, कल्याण योजनाओं का लाभ और जागरूकता अभियान चलाना।

नशा मुक्ति केंद्र

पुनर्वास, परामर्श, चिकित्सा सहायता और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने वाले राज्यव्यापी केन्द्रों के माध्यम से नशा प्रवृत्ति को कम करना।

सामाजिक न्याय और कल्याण

बढ़ती वृद्ध जनसंख्या

राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या 2011 में 5.1 मिलियन से बढ़कर 2047 तक 13 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे सशक्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था एवं वृद्धजन देखभाल उपायों की आवश्यकता होगी, जैसे – वृद्धावस्था पेंशन।

निराश्रित बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

पालनहार योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक बच्चों को मासिक नकद सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही फॉस्टर केयर एवं संस्थागत कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर बच्चों को आवश्यक सहयोग एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

समग्र कल्याण ढांचा

राजस्थान की 30% आबादी कमजोर वर्गों से है। राज्य की नीतियाँ, कानून और सामाजिक कार्यक्रम इन समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करते हैं।

शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता

प्राथमिक शिक्षा में SC और OBC छात्रों ने सशक्त प्रदर्शन दिखाया है, जो उनकी अपार संभावनाओं को दर्शाता है। निरंतर समर्थन एवं लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर लर्निंग आउटकम्स को बनाये रखने एवं उन्हें अधिक बेहतर बनाने हेतु अवसर मौजूद हैं।

अल्पसंख्यक मामलात

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा तक पहुंच

सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन (6.88%) उनकी जनसंख्या (11.40%) की तुलना में कम है। इस अंतर को कम करने हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा 32 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 3,427 छात्रों का नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3,696 मदरसों के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे नामांकन दर में सुधार हुआ है। अल्पसंख्यक छात्रावासों की स्थापना, छात्रवृत्ति वितरण एवं स्कूटी प्रदान करने जैसी पहलों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा को और सशक्त किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना

अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक सशक्त बनाने एवं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ऋण सुविधाएं, मार्केट लिंकेजेस तथा व्यापार समर्थन कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिससे वित्तीय असमानता में कमी हुई है तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

अवसंरचनात्मक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं का विकास हुआ है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग (RSCM) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं प्रगति सुनिश्चित की जा रही है।

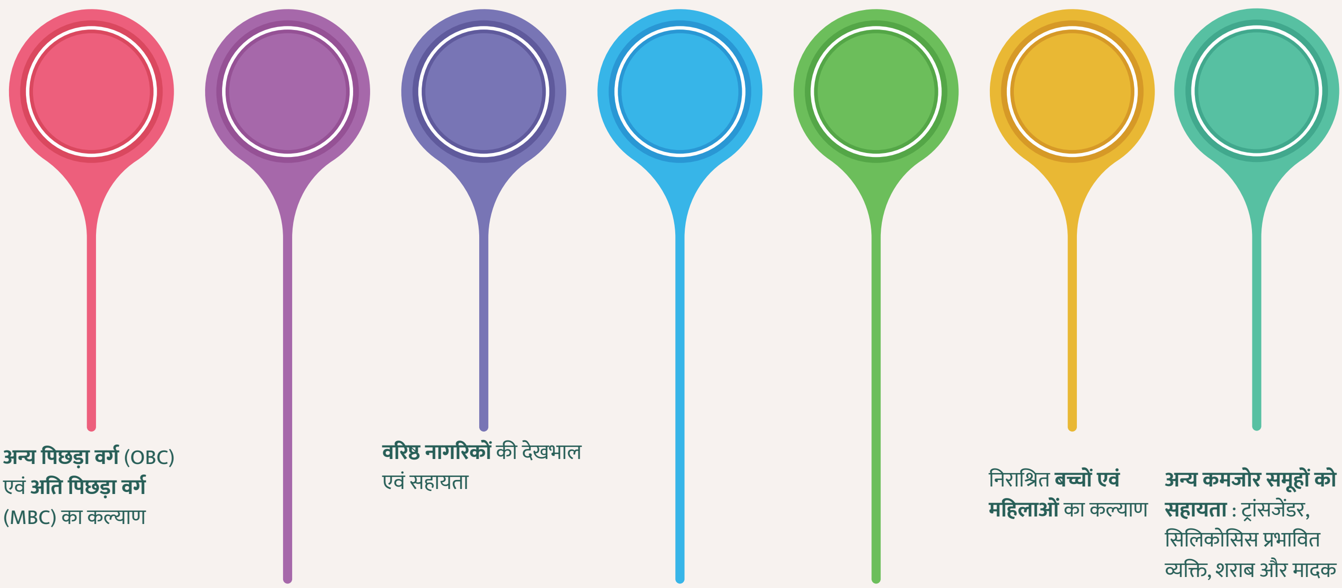

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता

संकेतक	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (2030)	लक्ष्य (2035)	लक्ष्य (2040)	लक्ष्य (2047)
वृद्धावस्था और डे केयर सेंटर आदि के माध्यम से संस्थागत सहायता की क्षमता (संख्या)	10,000	30,000	40,000	50,000	1,00,000
संतृप्ति दृष्टिकोण द्वारा स्मार्ट प्रणाली के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक पेंशन	61 लाख	85%	90%	95%	100%
पेंशन पाने वाली विधवाओं की संख्या	23 लाख	85%	90%	95%	100%
पेंशन पाने वाले विशेष योग्यजनों की संख्या	6.4 लाख	80%	90%	95%	100%
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चे	7.0 लाख	80%	90%	95%	100%
विशेष योग्यजन बच्चों का नामांकन अनुपात (%)	47	70	80	85	100
पहचाने गए विशेष योग्यजनों का प्रमाणन (%)	30	70	80	85	100
सिलिकोसिस मुआवजा (संख्या)	18,274	7,125	5,500	4,660	1,500

महिला एवं बाल विकास

संकेतक	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (2030)	लक्ष्य (2035)	लक्ष्य (2040)	लक्ष्य (2047)
जन्म के समय लिंगानुपात	920	930	935	940	>950
12–23 माह की आयु की पूर्ण टीकाकरण प्राप्त कर चुकी बालिकाएं (%)	81	>85	>90	>95	100
5 वर्ष से कम आयु के नाटापन (stunted) वाले बच्चे (%)	32	<20	<15	<10	<5
5 वर्ष से कम आयु के दुबलापन (wasted) वाले बच्चे (%)	17	<10	<7	<5	<1
5 वर्ष से कम आयु के कम वज़न वाले (underweight) बच्चे (%)	28	<15	<12	<10	<5
15–19 वर्ष की किशोरियों में एनीमिया की व्यापकता (<12.0 g/dl) (%)	59	<40	<25	<15	<5
महिला श्रम बल भागीदारी दर (%)	33.2	35	40	>45	>60
20–24 वर्ष की ऐसी महिलाएं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह किया (%)	25.4	<15	<10	<5	0
राज्य विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)	10	>20	>25	>30	>40

सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

VIKSIT RAJASTHAN @2047

VISION STATEMENT
VIKSIT RAJASTHAN@2047

"By 2047, Rajasthan will emerge as a leading state of New India-marked by inclusive growth, empowered citizens, world-class infrastructure, sustainable development and transparent governance, rooted in its rich cultural heritage and driven by the pioneering spirit of the people of the Rajasthan."

Haribhau Bagde

"It brings me immense pleasure to present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document to all of you.
I believe that this vision document is a roadmap for the aspirations, expectations and future development journey of the State by 2047. This is not a policy document but a collective resolve to shape Rajasthan as a model of prosperity, sustainability and inclusive development."

Rajasthan is a land of glorious cultural heritage, a dynamic economy and people with a strong determination for development. The State's development vision sets ambitious yet achievable goals, demonstrating its ability to turn challenges into opportunities. We envision Rajasthan's development to be inclusive and future-oriented. In line with this vision, special emphasis has been laid on strengthening Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), encouraging innovation and entrepreneurship, empowering women and youth, promoting green infrastructure and conserving our precious natural resources.

To advance this ambitious agenda, various departments have prepared their respective vision documents through extensive consultations with stakeholders, sector experts and departmental officials by incorporating meaningful suggestions from the public. Through this collaborative effort and the active participation of 45 departments, the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document has been prepared by the Rajasthan Institute for Transformation and Innovation (RITI).

After extensive deliberations at the level of the Hon'ble Chief Minister and the Chief Secretary, this document was finalised and formally approved by the State Cabinet on 23rd August 2025.

This ambitious transformation requires not only the efforts of the government, but also the active participation of citizens, policymakers, industries, academia and civil societies. With collective resolve and a unified vision for progress, Rajasthan has the potential to become a leading contributor to India's growth story and a symbol of sustainable and inclusive prosperity for the world.

Let us all come together with determination to realise the vision of 'Viksit Rajasthan@2047' and build a prosperous, sustainable and future-ready Rajasthan for generations to come.

Haribhau Bagde
Governor, Rajasthan

Bhajan Lal Sharma

"I am honoured to unveil the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document, which aims to transform Rajasthan into a thriving state and a model of inclusive development by 2047."

It is with great pride that I present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document- a roadmap to transform Rajasthan into a beacon of economic prosperity, sustainable development and inclusive growth. This vision is deeply aligned with the national aspirations of 'Viksit Bharat@2047' and through this document, we reaffirm our commitment to build an empowered, self-sufficient and developed Rajasthan.

Our state, rich in cultural heritage, diverse landscapes and entrepreneurial spirit, has the potential to become a leading force in India's growth story. Rajasthan has consistently demonstrated economic dynamism, ranking among the fastest-growing state economies. To harness this potential, we must focus on strategic reforms, technological advancements and sustainable practices that drive long-term development.

The 'Viksit Rajasthan@2047' vision encompasses key sectors such as industry, education, healthcare, infrastructure and environmental sustainability. Our priorities include strengthening MSMEs, fostering innovation, expanding clean energy projects, enhancing digital governance and ensuring inclusive social development. We remain committed to water conservation, green infrastructure and empowering women, youth and farmers of Rajasthan.

This transformation requires collective effort. I urge all citizens, businesses, policymakers and institutions to join hands in shaping Rajasthan's future. Let us move forward with unity, determination and innovation, ensuring that by 2047, Rajasthan stands as a model of progress and prosperity for India and the world.

Together, we shall make 'Viksit Rajasthan@2047' a reality.

Bhajan Lal Sharma
Chief Minister, Rajasthan

Sudhansh Pant

"I am pleased to present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document, which outlines a strategic roadmap for the state's development, aligning with the celebration of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav.'"

It is my privilege to present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document, a comprehensive roadmap for the State's long-term growth and development. This document aligns with the national vision of 'Viksit Bharat@2047', reinforcing Rajasthan's commitment to sustainable progress and inclusive prosperity.

Built on the aspirations of citizens, policymakers and industry leaders, this vision focuses on thirteen key sectors that constitute the foundation of Rajasthan's transformation. These include economic growth, industrial expansion, digital innovation, education, healthcare, infrastructure, tourism, environmental sustainability, water security and governance reforms. The State aims to establish a robust, future-ready economy that fosters innovation, entrepreneurship and equitable opportunities for all.

Rajasthan has already emerged as a major contributor to India's economy and a hub for renewable energy, tourism and industrial development. However, achieving our ambitious targets will require strategic reforms, investments and strong public-private partnerships. Through clean energy initiatives, water conservation programmes, SMART urbanisation and youth-driven entrepreneurship, Rajasthan will lead the way towards a sustainable and digitally empowered future.

This vision is not just a plan – it is a call to action. I extend my sincere appreciation to the Government officials, NITI Aayog, industry experts, academia and civil society for their contributions in shaping this document. I urge all stakeholders to actively participate in this transformative journey, ensuring that Rajasthan emerges as a leader in India's growth story by 2047.

Together, let us build a Viksit Rajasthan–prosperous, inclusive and future-ready.

Sudhansh Pant

Sudhansh Pant
Chief Secretary
Government of Rajasthan

Bhawani Singh Detha

"It is my privilege to present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document that outlines the future of Rajasthan by 2047. The document embodies a dedication to achieve aspirational goals. Each vision tailored to specific sectors is supported by a strategic roadmap, making certain that all elements of Rajasthan's growth and development are incorporated."

It is my honour to present the 'Viksit Rajasthan@2047' vision document, a blueprint for the state's long-term development and created by the Rajasthan Institute for Transformation and Innovation (RITI). As the state's premier policy think tank, RITI has played a pivotal role in formulating this roadmap, ensuring that it reflects aspirational yet achievable goals across key sectors.

Aligned with the national vision of 'Viksit Bharat@2047', this document charts a course for economic growth, social progress, technological advancement, environmental sustainability and governance reforms. It provides sector-specific roadmaps to guide policy decisions, investment priorities and developmental strategies by 2047.

The vision for Amrit Kaal, set forth by the Hon'ble Prime Minister, calls for a collaborative, future-ready approach to transform India. Rajasthan, with its rich heritage, vast potential and strategic strengths, will be a key driver in this national mission. The 'Viksit Rajasthan@2047' document will serve as a guiding framework for all government departments, industries and stakeholders as they align their efforts towards sustainable and inclusive growth.

I extend my sincere gratitude to all officials, experts and contributors who have shaped this vision.

Together, let us work towards a Rajasthan that is prosperous, resilient and globally competitive by 2047

Bhawani Singh Detha
Principal Secretary, Planning
Government of Rajasthan

SOCIAL EMPOWERMENT & INCLUSION

MOVING TOWARDS
SOCIAL SECURITY & INCLUSION

Rajasthan is committed to **inclusive social development, ensuring the welfare of marginalised communities, women, children, labourers, minorities, youth and specially abled person.**

With dedicated departments for **tribal, minority, labour, women and child development and youth affairs,** the state focuses on **education, healthcare, employment, sports and gender equality.** Policies and schemes aim at **economic upliftment, social justice and workforce empowerment, fostering a progressive and inclusive Rajasthan by 2047.**

92.38 lakh
(Census 2011)
Scheduled Tribe population
(13.5% of state population)

122.21 lakh
(Census 2011)
Scheduled Caste population
(17.83% of state population)

Minority population
78.18 lakh
(Census 2011)
(11.41% of total state population)

Dedicated Department for Child Rights established in 2014

5th Schedule grants
Rajasthan special powers for tribal governance

Women-focused policies
on health, education, skilling and protection

Labour Department ensures fair wages and industrial harmony

Skill development
for youth through
'Rajasthan Skill Policy 2025'

Tribal Area Development Department established in 1975 for tribal upliftment

Dedicated Department for Minorities
established in 2009

Modern sports infrastructure
to foster youth fitness and excellence

VISION 2047

By 2047, Rajasthan will be a **more equitable, inclusive and prosperous state,** ensuring holistic development for all, especially **weaker and vulnerable sections.** Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Minorities will be **socially, politically and economically empowered** and women and children **will have equitable access to opportunities and live life full of dignity and complete sense of security.**

A resilient **workforce and skilled youth** will drive **economic growth. Sports, fitness and talent development will be prioritised, ensuring global excellence and national recognition for Rajasthan.**

Thrust Areas

Empowering Weaker Sections

Rajasthan is committed to uplifting marginalised communities through education, skilling and employment opportunities.

Empowerment of Specially Abled Person

Expanding inclusive education, skill training and financial aid to ensure equal opportunities.

Senior Citizen Welfare

Establishing care homes, healthcare support and social security benefits for the elderly population.

Women & Child Welfare

Strengthening social safety net and socio-economic-political empowerment for women and children, including most vulnerable.

Maternal & Child Health

Promoting improved nutrition and healthcare to ensure better survival and developmental outcomes for women and children.

Beggar Free Rajasthan

Eliminate beggary by identifying & rehabilitating beggars through shelter, food, skill development and NGO-supported social reintegration.

DNT (Denotified Tribes) Welfare

Enhance the socio-economic status of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes through welfare schemes, skill development and mainstream inclusion.

Minority Upliftment

Enhancing education in Madarsas, providing livelihood opportunities and developing basic infrastructure in minority-dominated areas.

Labour Rights & Welfare

Promoting social protection and enforcing strong labour laws for worker security.

Youth & Sports Development

Investing in world-class sports infrastructure, athlete support and talent identification programs.

Sustainable Tourism & Indigenous Identity

Promoting eco-friendly tourism while preserving tribal culture and indigenous knowledge.

Climate Resilience & Social Well-being

Implementing climate adaptation strategies, environmental conservation and integrating women in climate action.

Transgender Welfare

The empowerment and inclusion of the transgender community through ID issuance, skill training, access to welfare schemes and awareness campaigns.

De-addiction Centres

Combating substance abuse through state-wide centres offering rehabilitation, counselling, medical support and community awareness programs.

Social Justice & Welfare

Rising Ageing Population

Rajasthan's senior citizen population is projected to grow from 5.1 million (2011) to 13 million (2047), demanding strong social security and elderly care measures i.e. Old-age pensions.

Expanding Social Safety for Destitute Children

The Palanhar scheme provides monthly cash assistance to 7 lakh+ children, alongside foster care and institutional programs to support vulnerable children needing care and protection.

Comprehensive Welfare Framework

With 30% of Rajasthan's population from weaker sections, state policies, laws and social programs ensure holistic development and empowerment of marginalised communities.

Educational Outcomes Need Focused Attention

SC and OBC students demonstrate strong performance in primary education, showcasing great potential. With continued support and targeted interventions, there is a significant opportunity to sustain and enhance learning outcomes at the elementary and secondary levels.

Minority Affairs

Expanding Access to Education for Minorities

Minority Student's enrolment in Government Schools is 6.88% lower than their 11.40% population. To Bridge the gap, Department of Minority Affairs started 32 Residential Schools having 3,427 students enrolled. Additionally, 3,696 Madrasas provide primary education to minority students, contributing to improved enrolment rates. Initiatives such as minority hostels, scholarships and scooty distribution further support the educational upliftment of minority communities.

Enhancing Minority Economic Participation

Loan facilities, market linkages and business support programs promote economic empowerment and employment opportunities for minority communities, reducing financial disparities and fostering self-sufficiency.

Infrastructure & Minority Rights Protection

Basic amenities are developed under PM Jan Vikas Karyakram. The Rajasthan State Commission for Minorities (RSCM) ensures protection and progress of minority communities.

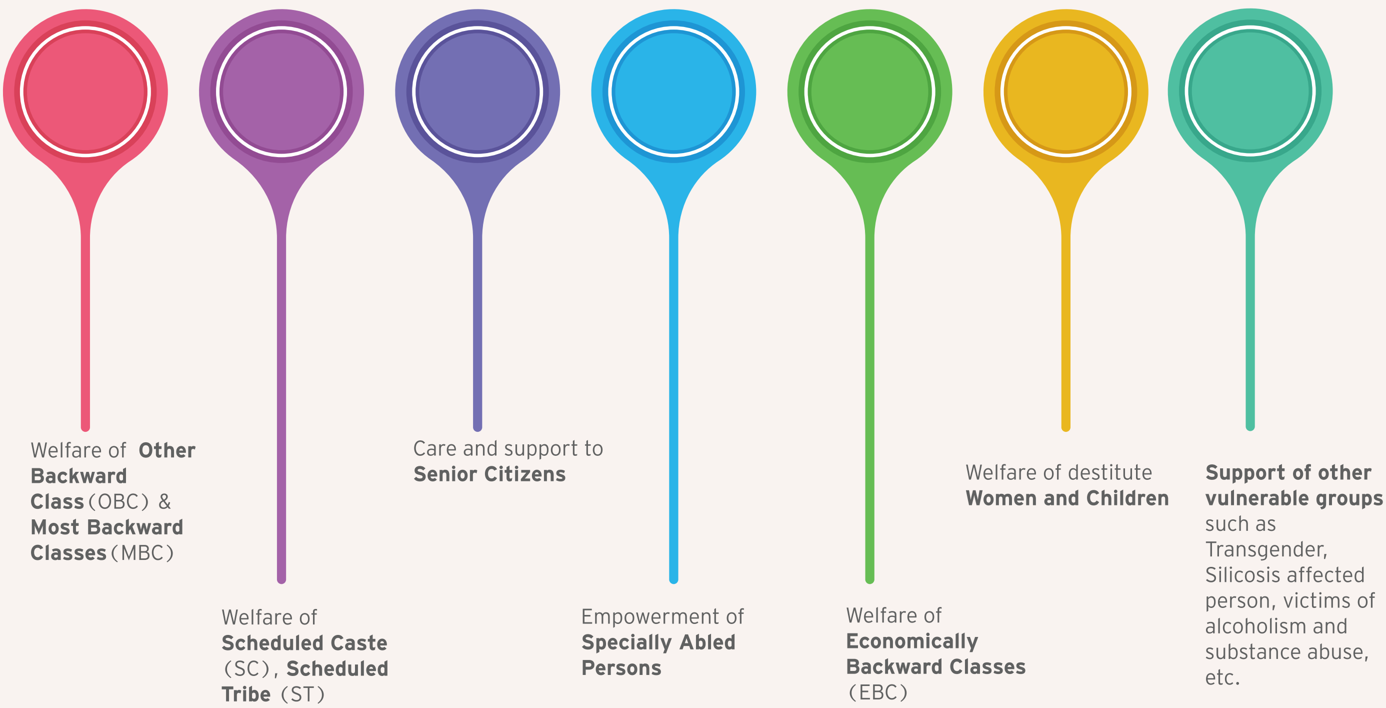

Social Justice and Empowerment

INDICATORS	CURRENT STATUS	TARGET (2030)	TARGET (2035)	TARGET (2040)	TARGET (2047)
Capacity for institutional assistance through old age and day care centers etc. (Numbers)	10,000	30,000	40,000	50,000	1,00,000
Senior Citizen pension through smart system by saturation approach	61 Lakh	85%	90%	95%	100%
Number of widows getting pension	23 Lakh	85%	90%	95%	100%
Number of specially abled getting pension	6.4 Lakh	80%	90%	95%	100%
SC/ST children covered by post-matric scholarships	7.0 Lakh	80%	90%	95%	100%
Enrolment ratio of children with specially abled children (%)	47	70	80	85	100
Certification of identified specially abled persons (%)	30	70	80	85	100
Silicosis compensation (Numbers)	18,274	7,125	5,500	4,660	1,500

Women and Child Development

INDICATORS	CURRENT STATUS	TARGET (2030)	TARGET (2035)	TARGET (2040)	TARGET (2047)
Sex ratio at birth	920	930	935	940	>950
Girl child aged 12-23 months who are fully vaccinated (%)	81	>85	>90	>95	100
Children under 5 years who are stunted (%)	32	<20	<15	<10	<5
Children under 5 years who are wasted (%)	17	<10	<7	<5	<1
Children under 5 years who are underweight (%)	28	<15	<12	<10	<5
Prevalence of anaemia among girls aged 15-19 years (<12.0 g/dl) (%)	59	<40	<25	<15	<5
Female labour force participation rate (%)	33.2	35	40	>45	>60
Women aged 20-24 years married before age 18 years (%)	25.4	<15	<10	<5	0
Seats held by women in state assembly (%)	10	>20	>25	>30	>40